अपने पौष्टिक तत्वों के लिये पूरी सतह से शक्ति प्राप्त करती हैं। इस प्रकार यह करोपिंग ढंग बहुत ही वैज्ञानिक है।

- (5) यह तरीका देश के उत्तरी भागों में छोटे किसानों के लिये बहुत ही उपयुक्त है और इससे छोटे फार्मों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे। मूंग के अतिरिक्त अन्य कोई भी खाद्यान्न की फसल केवल दो सिचाई से गर्मी के महीनों में पूरी नहीं हो सकती है जिससे फार्म के पशुओं के लिये अधिक प्रोटीनयुक्त फलदार वारा उपलब्ध हो सकेगा। इससे गर्मी के महीनों में चारे की कमी भी कुछ पूरी होगी।
- (6) क्योंकि फसलें बहुत जल्दी-जल्दी बोई जाती हैं, इसलिये खपतवार दबे जाते हैं।
- (7) रिले करौपिंग की तकनीकी 'कुओं से सींचित' क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जा सकती हैं, साथ ही नहर से सींचित क्षेत्रों में भी जहां पर सिचाई का प्रबन्ध सुनिश्चित है।
- (ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—
 - (1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भारत में कृषि अनुसंधान विषयक अपने स्पेशल न्यूज विशेषांकों के माध्यम से उपरोक्त बहुविध तकनीकों का विस्तृत प्रचार किया गया है। ये विशेषांक 29 दिसम्बर 1967 को अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रमुख भाषाओं के 30 समाचार पत्नों में छपे हैं जो 20 लाख से भी अधिक माता में छपते हैं।

- (2) क्रापिंग तकनीक को आकाझवाणी से प्रसारित किया गया है और उसे कृषकों को बताने के लिये आकाश-वाणी के टेलीवीजन केन्द्र से भी, प्रसारित किया गया।
- (3) बहुत-से कृषकों को उनकी प्रार्थना पर रिले कार्पिग की साइकलोस्टाइल करवा कर उन्हें भेजा गया।
- (4) मूंग बैसाखी के बीज के नमूने 500 से अधिक कृषकों को दिये गये। कृषिकों को आवश्यक निर्देश भी दिये गये कि वे इसे गिमयों के महीनों में और फिर मानसून ऋतु में उगायें तािक 1969 के गर्मी के मौसम में उनके पास स्वयं अपना बीज उपलब्ध हो सके।
- (5) संस्था के स्टाफ की प्रत्यक्ष देखरेख में दिल्ली संघक्षेत्र में 4-5 मार्गदर्शी प्रदर्शनों की व्यवस्था की गई है।

CREDIT FACILITIES IN AGRICULTURE

4643. SHRI D N. PATODIA: Will the Minister of FOOD AND AGRI-CULTURE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that while credit relaxations had taken place in other sectors of economy it has not been introduced in respect of foodgrains, oilseeds, pulses which is affecting the functioning of the trade adversely;
- (b) whether the Reserve Bank of India has been impressed upon to consider this issue; and
 - (c) if so, its reaction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI RANNASAHIB SHINDE): (a) Credit relaxations have taken place in certain priority sectors such as (i) credit for

exports (both pre-shipment and post-shipment), (ii) for agricultural inputs (fertilisers and pesticides), and (iii) to small scale industries guaranteed by the Credit Guarantee Organisation. In the case of groundnut and certain other oilseeds, the control on advances has been modified in the current year in the light of good crops and appreciable fall in prices. So far as cereals and pulses are concerned, the continuation of the existing restrictions is considered necessary in order to discourage hoarding tendency.

(b) and (c) Do not arise.

नागालैण्ड में फलों की खेती

4644. श्री शशि भूषण वाजपेयी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागालैंड में फलों की खेती तथा उनके स्टोर की व्यवस्था और ढुलाई के लिये सरकार क्या सहायता देती है अथवा देने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्द्रालय में राज्य मन्द्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) नागालैंड में फलों की खेती और उनके स्टोर की व्यवस्था के लिये स्टेट प्लान स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने 1968-69 में कियान्वित करने के लिये अपनी वार्षिक प्लान के प्रारूप में निम्नलिखित स्कीमों को णामिल किया है:—

स्कीम का नाम	1968-69 के लिये प्रास्ताविक व्यय
बागबानी विकास स्कीम	1.50
सन्तति फलोद्यान एवं नर्सरी	1.50
फल परिरक्षण फैक्टरी	2.00
सन्तरे व अननास की खेती	0,60
ठण्डे गोदाम	0.86

नागालैंड राज्य की प्लान के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये विशेष प्रबन्ध है जिसके अन्तर्गत राजस्व व्यय केन्द्रीय अनुदान और पूंजी व्यय केन्द्रीय ऋण सहायता से पूरा किया जाता है।

खाद्याच्न को स्टोर करने की सुविधायें

4645. श्री शशि भूषण वाजपेयी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार किसानों को इस प्रकार की सुविधायें देने का है जिससे उन्हें उचित किराया लेने वाले भाण्डागारों में उस अविध के लिये खाद्यान्न को स्टोर करने में सहायता मिल सके जिसमें सट्टेबाब खाद्यान्न की कीमतों की कम दरें बनाये रखते हैं; और
- (ख) क्या सरकार का विचार किसानों को, जब तक उन्हें अपने उत्पादन की उचित कीमतें नहीं मिलती हैं, कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुवायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्वे): (क) और (ख): केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा राज्य भाण्डागार निगमों ने बहुत-से भाण्डारगार बनवाये हैं जहां किसान अपनी कृषि उपज को उचित किराये पर रख सकते हैं। इस बारे में उल्लिखित सुविधायें पहले से मौजूद हैं। जमाकर्ता केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों की भाण्डागार रसीदों पर बैंकों से ऋण तथा पेशगियां ले सकते हैं।

वकील परिषद्की परीक्षा

4646. श्री हुकम चन्द कछशाबाय : न्या